EXCLUSIVE

NEWS ANALYSIS BY

Mr. Shridhant Joshi

कौटिल्य एकेडमी

कौटिल्य एकेडमी

दैनिक भास्कर, इंदौर, गुरुवार, 20 दिसंबर 2018

भाजपा के सामने चुनौती, कांग्रेस के लिए मौका

संदर्भः भाजपा से मतदाता निराश है पर गुस्सा नहीं, दूर हो गए मतदाताओं को वापस लाने की रणनीति जरूरी

चेतन भगत
अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

कॉलम लेखक होने की एक मजेदार बात यह है कि चुनाव का वक्त आते ही लोग आपसे लगभग भविष्यवक्ता हो जाने की अपेक्षा करने लगते हैं। इन दिनों मैं जहां भी जाता हूं, चाहे मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाऊं या एयरपोर्ट या मित्रों के बीच 'क्या लग रहा है?' से लेकर 'अच्छा यह बताओ फाइनली कौन जितेगा?' जैसे सवाल शुरू हो जाते हैं। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद 2019 के चुनाव अचानक और भी ज्यादा रोमांचक हो गए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की हैट्रिक का लोकसभा चुनाव पर असर तो होगा। न सिर्फ इससे भाजपा के गिरते वोट शेयर का पता चलता है बल्कि इससे कांग्रेस का भी मनोबल और उत्साह बढ़ा है, जिन्होंने दो साल पहले हार मान ली थी। नोटबंदी के बाद जब मोदी ने उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव जीत लिए थे तो लोग 2019 में भाजपा की आसान जीत का पूर्वानुमान लगाने लगे थे। इसलिए 2019 में क्या होगा इसका जवाब देने के पहले असली सवाल तो ये हैं :

1. सिर्फ डेढ़ साल में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा वहां हार गई, जहां इसने 2014 में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया था? हिंदी क्षेत्र में ही इसके ज्यादा समर्थक हैं और जिन्होंने 2014 में पार्टी को लगभग परफेक्ट स्कोर दिया था। 2. क्या मोदी अचानक अलोकप्रिय हो गए हैं? 3. क्या सरकार की कोई नीति या योजना ऐसी रही जिसे लोगों ने खासतौर पर नापसंद किया? 4. हो सकता है इस सबका कोई महत्व न हो और हम राज्यों के चुनावों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि भारतीय मतदाता राज्यों व केंद्र के चुनाव का फर्क अच्छी तरह जानता है और संभव है वह लोकसभा चुनाव में अलग तरह से मतदान करें?

एक, क्या बदला है? कोई एक कारण तो नहीं है पर लगता है कि वोट देने वाले कई लोग (खासतौर पर वे जो पाला बदलकर भाजपा के समर्थक हो गए अथवा जिन्होंने पहली बार में उसे वोट देने वाले) भाजपा से निराश हो गए। गौरतलब है कि यह मामला निराशा का है, नफरत का नहीं। भाजपा के खिलाफ वैसा गुस्सा नहीं है, जैसा 2014 में यूपीए के खिलाफ था। फिर भी चूंकि इन मतदाताओं में से कई ने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया था या पहली बार दिया है, तो भाजपा के प्रति उनकी वफादारी निश्चित नहीं थी। सिर्फ निराश होना ही उन्हें अपनी पहले वाली पार्टी की ओर लौटने के लिए या किसी नई पार्टी को आजमाने के लिए काफी था, यदि उन्होंने इसके पहले कभी वोट ही नहीं दिया है तो। इस गतिशील नए वोटर और वे जो पाला बदलकर आए थे, उनकी उपेक्षा करने से भाजपा को वे कुछ प्रतिशत अंक कम पड़ गए, जो राज्यों के चुनाव जीतने के लिए जरूरी थे। मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए। वहां भाजपा ने 2013 में 45 फीसदी वोट शेयर के साथ बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 36 फीसदी वोट मिले थे। इस बार भाजपा का वोट शेयर गिरकर 41 फीसदी हो गया और कांग्रेस बढ़कर 41 फीसदी पर पहुंच गई। फिर भी कांग्रेस 114 सीटें पाने में कामयाब हो गई, जबकि भाजपा को 109 सीटें मिली। वोटों में यह 4 फीसदी कमी किसी सरकार को गिराने के लिए काफी थी। इसलिए जवाब यह है कि भाजपा के साथ कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है। मतदाताओं के एक वर्ग में निराशा जरूर है, जिससे वे उस पार्टी से दूर चले गए, जिसके वे कभी पूरी तरह थे ही नहीं। यह निश्चित ही भाजपा के लिए चिंताजनक है, क्योंकि लोग यदि राज्यों व केंद्र के चुनावों को अलग तरीके से देखें भी तो इस निराश वोटर को गंवाना लोकसभा चुनाव में भी समस्या पैदा करेगा।

कुछ वोटर निराश या हताश क्यों हैं? ज्यादातर इसलिए, क्योंकि 2014 में जब सरकार चुनी गई तो उन्हें बहुत अपेक्षा थी। भाजपा के वोटों में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी कमी आई है। परम्परागत रूप से भाजपा को बहुत समर्थन देने वाले मध्य वर्ग को भी लगा कि उसे कोई बड़ा फायदा नहीं मिला बल्कि जब से 2014 में नई सरकार आई है, ऊंचे आयकर और शुल्कों से उसे सजा ही मिली है। क्योंकि भ्रष्टाचार कम होने का दावा किया जा रहा है तो बचत का वह सारा अतिरिक्त पैसा कहां है? इसे मध्य वर्ग को टैक्स में कमी अथवा कम कीमतों (जैसे पेट्रोल) के रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब साढ़े चार साल गुजर जाते हैं और यह नहीं होता, जब लोगों को लगता है कि सरकार उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती, तो एक वर्ग सोचने लगता है कि इस सरकार में ऐसी क्या खास बात है कि मैंने अपनी पार्टी बदलकर इसे वोट दिया? इन मतदाताओं को कायम रखने में भाजपा सरकार कामयाब नहीं हो पाई। जीएसटी भी ऐसी बात है, जिसे कई व्यापारी पसंद नहीं करते, हालांकि इसकी स्वीकार्यता समय के साथ बढ़ती जा रही है। व्हाइट गुड्स जैसी आवश्यक वस्तुओं पर 28 फीसदी जीएसटी बड़ा बोझ लगता है खासतौर पर तब जब कोई खरीदी पर पहले ही टैक्स चुकाने के बाद पैसा खर्च कर रहा हो। फिर सवाल उठता है कि जब भ्रष्टाचार घट रहा है और सरकार कहती है कि कार्यकुशलता और आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही है तो टैक्स क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है।

कुछ मतदाताओं में निराशा का अन्य कारण है हिंदुत्व का संदेश देने के स्तर पर नियंत्रण रखने में सरकार की नाकामी। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व का तत्व भारतीय सब्जी में हरी मिर्च की तरह है। थोड़ी मात्रा सनसनाहट और स्वाद ला देती है। ज्यादा हो जाए तो आप भाग खड़े होते हैं और एक गिलास पानी पीना चाहते हैं। मंदिर जाना ठीक है। कभी-कभार तिलक लगाना भी गलत नहीं है लेकिन, अली/ बजरंग बली जैसी बांटने वाली बातें ठीक नहीं हैं। पार्टी ने 2014 में जो नाजुक संतुलन कायम किया था, वह अब नहीं है। योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना बहुत बड़ी घोषणा थी कि हम ऐसे ही हैं। इसने व्यंजन में तीन मिर्चियां झोंक दी, जिससे लोग भाग गए। विपक्ष ने ज्यादा हिंदुत्व से घबराए लोगों को आकर्षित किया। उलटफेर के लिए इतना काफी था।

भाजपा कुछ संकट में होगी लेकिन, कार में सच में कोई खराबी नहीं आई है। इंजन को फिर ट्यून करने की जरूरत है। दूर चले गए मतदाताओं को वापस लाने के लिए रणनीति बनानी होगी। इस बीच, कांग्रेस के पास भी 2019 के लिए बहुत अच्छा अवसर है, जो सालभर पहले उन्हें कोई नहीं देता। राजनीति के खेल को पसंद करने वाले हम जैसे लोगों के लिए इसका मतलब है मई 2019 में महा रोमांचक मैच। सर्वश्रेष्ठ टीम की जीत हो यही कामना है! **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

कौटिल्य एकेडमी

संपादकीय

जीएसटी की अर्थनीति और आगामी लोकसभा चुनाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक से चार दिन पहले मुंबई में यह संकेत दे दिया कि 99 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत यानी सबसे निम्न कर श्रेणी में रखी जाएंगी। जीएसटी परिषद के यह निर्णय लेने के बाद एअर कंडीशनर, डिश वॉशर और डिजिटल कैमरे भी सस्ते हो जाएंगे। वैसे सबसे ऊपर, यानी 28 प्रतिशत कर के दायरे में आरंभ में 1211 वस्तुएं थीं और अब घटकर महज 37 रह गई हैं। मौजूदा निर्णय के बाद उच्च श्रेणी में निजी विमान, याट, रिवॉल्वर जैसी महज 6-7 चीजें ही रह जाएंगी। प्रधानमंत्री की दलील है कि जीएसटी कर प्रणाली काफी कुछ स्थिर हो चुकी है, कराधान का आधार व्यापक हो चुका है इसलिए करों को घटाने की जरूरत है। उन्होंने माना है कि अब कर चोरी घट गई है और वसूली अच्छी खासी हो रही है। लेकिन जिस हिंदी इलाके के तीन राज्य गंवाने के बाद भाजपा चौकस हुई है, उसमें इस फैसले को हार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को बड़ा मुद्दा बनाया था। वे तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक कहते रहे। जीएसटी के असर में उद्योगों को परेशानी हुई है और नौकरियों में गिरावट भी आई है। इस तरह के निष्कर्ष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के संगठनों ने भी निकाले हैं। जीएसटी कम होना व्यापारियों और आम जन को किस हद तक राहत देगा यह अभी देखा जाना है, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि सीमेंट जैसी वस्तु में जीएसटी की कटौती से 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए सालाना हानि होगी। पिछले साल एक जुलाई को धूम-धड़ाके के साथ शुरू किए गए जीएसटी जैसे देश के सबसे बड़े कर सुधार में अक्तूबर, नवंबर, जनवरी और जुलाई मिलाकर चार बार संशोधन हो चुका है। कई सामानों को उच्च श्रेणी के करों से निकाल निम्न श्रेणी में डाला गया है। इससे उपभोक्ताओं को तो राहत मिली है लेकिन करीब 90 हजार करोड़ रु. के कर की हानि केंद्र और राज्यों को हुई है। मौजूदा संशोधन से चौंके केरल और दूसरे राज्यों ने आपत्ति भी की है। उनका कहना है कि जीएसटी के आरंभ में ही सुझाव आया था कि ज्यादा श्रेणियां और ऊंचे कर समस्या पैदा करेंगे। वह अब सामने आ रहा है। तेल और शराब को इस दायरे में लाने की मांग अभी लंबित ही है। लगता है जीएसटी पर राजनीति का प्रभाव पड़ रहा है और उसकी सकारात्मक अर्थनीति को दिखने में अभी भी वक्त है।

कौटिल्य एकेडमी

नीति आयोग ने 'नए भारत के लिए रणनीति' विषय पर दस्तावेज जारी किया

कर्ज माफी का लाभ 10-15% किसानों को: नीति आयोग

रिजर्व प्राइस तय करके मंडियों में फसलों की नीलामी का सुझाव

एजेंसी | नई दिल्ली

कृषि कर्ज माफी पर छिड़ी बहस में नीति आयोग भी शामिल हो गया है। इसका कहना है कि कर्ज माफी से समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि इसका लाभ बहुत कम किसानों को मिलता है। बुधवार को 'नए भारत के लिए रणनीति' विषय पर दस्तावेज जारी करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही कहा था कि वह तब तक प्रधानमंत्री मोदी को चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं होते।

आयोग में कृषि मामलों के विशेषज्ञ रमेश चंद ने कहा कि गरीब राज्यों में कर्ज माफी का लाभ सिर्फ 10-15% किसानों को मिलता है। वहां बहुत कम किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की मांग इसलिए उठती है क्योंकि किसानों की आमदनी पर्याप्त नहीं बढ़ रही है। 'नए भारत के लिए रणनीति' एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया है कि कैसे 8% जीडीपी ग्रोथ हासिल करके 2030 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर (350 लाख करोड़ रु.) की इकोनॉमी बनाया जा सकता है। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडियों में न्यूनतम रिजर्व प्राइस तय करके फसलों की नीलामी का सुझाव दिया है। सरकार को एमएसपी का सुझाव देने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जगह कृषि ट्रिब्यूनल बनाने की सिफारिश है।

डिजिटाइजेशनः 20122-23 तक सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल कनेक्टिविटी हो। सरकारी सेवाओं की डिलीवरी डिजिटल तरीके से हो। अभी बहुत सी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं। देश में 35.5 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। यह कुल आबादी का 27% है। इसे बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

साइबर सुरक्षाः साइबर सुरक्षा का रेगुलेटरी ढांचा कमजोर है। हैकिंग के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवाएं बाधित हुई हैं। बैंकों और सरकारों पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

स्पेक्ट्रमः बेहतर सर्विस क्वालिटी के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम जरूरी है। अभी नेटवर्क स्पेक्ट्रम की कमी से जूझ रहे हैं। 'ट्राई को कॉल ड्रॉप की पहचान करने के लिए उचित व्यवस्था बनानी चाहिए। ब्रॉडबैंड के लिए 512 केबीपीएस की स्पीड पर्याप्त नहीं है। शिकायतें दूर करने के लिए दूरसंचार लोकपाल बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

जेटली बोले सिर्फ नारों से गरीबी दूर नहीं होगी

विपक्ष पर हमला करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि बेहतर नीति से गरीबी दूर होगी। लोगों को जल्दी नारों की असलियत मालूम पड़ जाती है। जेटली नीति आयोग का डॉक्यूमेंट जारी करते समय मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी।

कौटिल्य एकेडमी

इसरो का जीसैट-7ए लॉन्च; अब एयरफोर्स के विमान हवा से हवा में रियल टाइम में कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ड्रोन भी इस सैटेलाइट से लिंक होंगे

जीएसएलवी रॉकेट से लगातार छठी सफल लॉन्चिंग, जनवरी में होने वाला चंद्रयान-2 मिशन टला

भास्कर न्यूज | श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश)

इसरो ने बुधवार शाम 4.10 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार उपग्रह जीसैट-7ए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। जीएसएलवी-एफ11 नामक रॉकेट ने इस उपग्रह को लॉन्चिंग के करीब 20 मिनट बाद अंतरिक्ष में अपनी तय कक्षा में पहुंचा दिया। श्रीहरिकोटा से ये इस साल की 7वीं और अंतिम लॉन्चिंग थी। यह उपग्रह वायु सेना की कम्युनिकेशन प्रणाली को और दुरुस्त बनाएगा। एयरक्राफ्ट के बीच हवा से हवा में वास्तविक समय में संपर्क हो सकेगा, ग्राउंड के जरिए संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी।

लॉन्चिंग के बाद भास्कर से बात करते हुए इसरो चेयरमैन के. सिवन ने कहा कि 35 दिनों के अंदर श्रीहरिकोटा से इसरो का यह तीसरा सफल प्रक्षेपण है। इस उपग्रह में ग्रिगोरियन एंटीना लगाया गया है। इसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए होगा। जीएसएलवी का यह लगातार छठा सफल मिशन था। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग डेट पूछने पर उन्होंने कहा कि तिथि तय करने में अभी कुछ वक्त लगेगा। सिवन ने अगस्त में कहा था कि चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग 3 जनवरी को होगी।

इसरो ने इस साल सात लॉन्चिंग की, अब अगले साल चंद्रयान-2 सहित 32 लॉन्चिंग करेगा

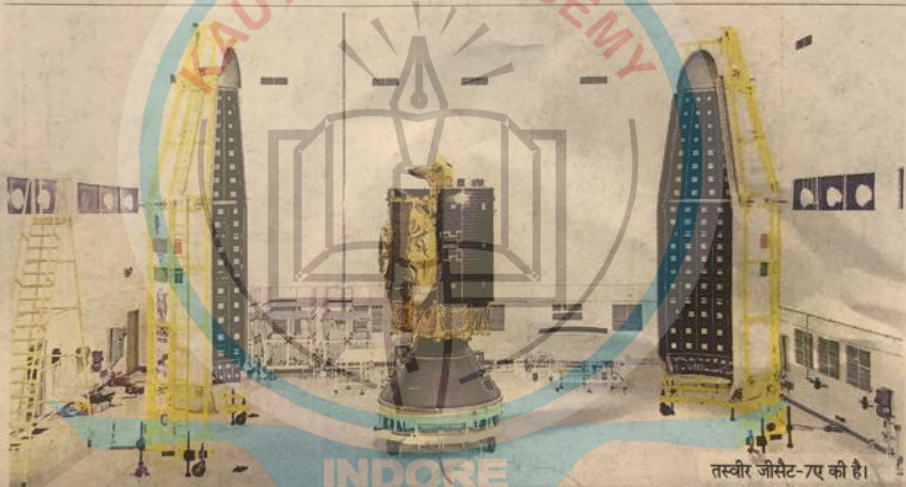

तस्वीर जीसैट-7ए की है।

35 दिनों में ये चार मिशन लॉन्च हुए

14 नवंबर : जीएसएलवी मार्क-3 डी-2 से जीसैट-29

29 नवंबर : पीएसएलवी सी-43 से हाइसिस

19 दिसंबर : जीएसएलवी एफ-11 से जीसैट-7ए

5 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना (विदेशी जमीन से) से जीसैट-11

क्या है जीसैट-7ए

2250 किलोग्राम वजन
पेलोड-केयू बैंड ट्रांसपोंडर्स
8 साल मिशन की अवधि
800 करोड़ रुपए की लागत

क्या करेगा जीसैट-7ए — एयरफोर्स की संपत्तियों को लिंक करेगा और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा

- रडार, एयरबेस और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को इंटरलिंक करेगा। हवा में एयरक्रॉफ्ट संपर्क कर सकेंगे।
- इसके जरिए लंबी दूरी में मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट और पोत का पता लग सकेगा।
- ड्रोन से वीडियो और इमेज लेकर ग्राउंड स्टेशन को भेजकर निगरानी में मदद करेगा।
- ये अन्य सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन के रडार और भारतीय समुद्री क्षेत्र के स्टेशन की कवरेज को बढ़ाएगा।
- लंबी दूरी में ड्रोन, यूएवी के जरिए एनिमी टारगेट पर हमले की रेंज बढ़ाने और नियंत्रण में मदद करेगा। भारत अमेरिका से गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है जो ऊंचाई से लक्ष्य पर हमला कर सकता है।

क्या है केयू बैंड का फायदा

- छोटे एंटीना से भी सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं।
- किसी अन्य बैंड की तुलना में ज्यादा बीम कवरेज देता है।
- बारिश व अन्य मौसमी व्यवधानों में कम प्रभावित होता है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

कौटिल्य एकेडमी

यमन में सुरक्षाबलों और हौती विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम का फरमान, लेकिन गोलीबारी हुई

सना | यमन में सुरक्षाबलों और हौती विद्रोहियों के बीच मंगलवार रात से युद्ध विराम का आदेश लागू हो गया। इसके बावजूद अल हुदयदा में कई हौती समर्थक हथियारों के साथ बुधवार को भी मोर्चा संभाले रहे। कुछ स्थानों से गोलीबारी की खबरें हैं। सऊदी सरकार के अल-अरबिया चैनल के मुताबिक हौती समर्थक समझौते पर अमल नहीं करना चाहते।

कौटिल्य एकेडमी

इलाज कुछ और

कर्ज माफ़ी जैसे सतही प्रयासों से भारतीय किसान की हालत नहीं सुधरेगी। वह सुधरेगी किसी ठोस नीति, युक्ति व संवेदनशील प्रशासन तंत्र बनाने से।

किसानों के कर्जों की माफ़ी इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया लगता है और माहौल कुछ ऐसा बन रहा है मानो किसानों के लिए तो बस अच्छे दिन आने को ही हैं। यह भरोसा कांग्रेस अध्यक्ष यह कहते हुए किसानों को दिला रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देंगे जब तक देश के सभी किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो जाते। इन तेवरों में तीन राज्यों में उनकी पार्टी के शासन में लौटने से आया आत्मविश्वास साफ़ झलकता है। शायद उन्हें यह लगता है कि लोकसभा चुनावों में वे इस मुद्दे से बड़ा सहारा पा सकते हैं। यही कारण है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में शासन में वापसी पर कांग्रेस सरकारों का पहला कदम किसानों के कर्ज माफ़ी का रहा। दलीय प्रतिस्पर्धा के चलते किसान कर्ज माफ़ी की होड़ लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। असम में भाजपा सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफ़ी की योजना बना ली है तो गुजरात सरकार ने किसानों के 625 करोड़ रुपयों के बिजली के बिलों की राशि माफ़ी की घोषणा की है। किसानों के कर्जों की माफ़ी का कदम लुभावना तो लगता है पर बड़ा सवाल है कि क्या इससे किसानों की मुश्किलें वास्तव में आसान हो सकती हैं? दिलचस्प है खुद राहुल गांधी, जो ऐसा कराने के लिए ताल ठोक कर लगे हैं, भी ऐसा नहीं मानते। राहुल कहते हैं, "कर्ज माफ़ी एक सपोर्टिंग स्टेप है कर्ज माफ़ी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ज्यादा नहीं हो रही है। कॉम्प्लेक्स होगा, आसान नहीं होगा।"

किसानों के लिए कर्ज माफ़ी पहली बार नहीं हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2008 में किसानों के 60,000 करोड़ रुपयों के कर्जे माफ़ किए थे। बाद में उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक ने किसानों के कर्जों को माफ़ करने की घोषणाएं की। ऐसे लोक लुभावने क़दमों से किसानों का बड़ा भला हो या न हो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव जरूर पड़ता है जिसका खामियाजा आम जन को भुगतता है। इसीलिए ऐसे क़दमों को अर्थशास्त्री ही नहीं कृषि विशेषज्ञ भी उचित नहीं मानते। अध्ययनों में सामने आया है कि ऐसे क़दमों से बड़ी व मध्यम हैसियत के किसान अधिक फायदे में रहते हैं। बैंकिंग विशेषज्ञ मानते हैं कि किसानों के कर्जों का साख चक्र होता है। किसी एक चक्र के दौरान कर्ज माफ़ी होती है तो अगले साख चक्र में छोटे सीमांत किसानों के लिए कर्ज की मात्रा घट जाती है। दूसरी तरफ किसानों की कर्ज माफ़ी के समर्थक इसे एक रणनीतिक मुद्दा मानते हैं जिसे रुपये-पैसे के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। वे अमरीकी अर्थव्यवस्था का हवाला देते हैं कि वहां सरकार किसानों को 30 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देती है। तो फिर भारतीय किसान की मदद क्यों न की जाय? बात सही है। आज हमारे यहां हालात ऐसे हैं कि खेती के अनिश्चित व्यवसाय में उसे कोई अपना करियर नहीं चुनता। अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी अब घट कर 17-18 प्रतिशत रह गई है। इसलिए गरीबी पर प्रभावी हमला भी कृषि को सुधारने और उसे बढ़ावा देने से ही संभव है। मगर उसका तरीका क्या हो? कोई भी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री या कृषि विशेषज्ञ कर्ज माफ़ी को इसका बेहतर तरीका नहीं मानेगा। किसान को यदि समय पर बिजली, पानी, बीज और खाद मिल जाए और उसे उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल जाए तो वह सहजता से कर्जा ही नहीं चुका पाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका भी अदा कर पाएगा। मगर सरकारें कृषि में वैसा निवेश नहीं करती जितना अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में करती है। कर्ज माफ़ी जैसे सतही प्रयासों से भारतीय किसान की हालत नहीं सुधरेगी। वह सुधरेगी किसी ठोस नीति और युक्ति से और एक संवेदनशील प्रशासन तंत्र बनाने से।

कौटिल्य एकेडमी

मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी : अल्पकालीन कर्ज शामिल, लेकिन दीर्घकालीन दरकिनार

कर्जा माफ, लेकिन सियासी गुणा-भाग भी साथ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. कर्नाटक, पंजाब और छत्तीसगढ़ की तरह मध्यप्रदेश में भी किसानों का अल्पकालीन कर्ज माफ किया गया है। यहां कांग्रेस सरकार के आते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद संभालने के तुरंत बाद किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया। इस दायरे में 34 लाख किसान आएंगे, लेकिन अभी इसके क्रियान्वयन में समय लगेगा। अभी कर्ज माफी को लेकर नए नियम तैयार नहीं हो पाए हैं। सरकार ने क्रियान्वयन के लिए 22 सदस्यीय समिति मुख्य सचिव बीपी सिंह की अध्यक्षता में बना दी है। इस समिति को एक्शन मोड में आने में समय लगना है, क्योंकि अभी तक कर्ज माफी के लिए पोर्टल तैयार नहीं हो सका है।

40 लाख का डाटा

मैपआईटी की टीम ने चंडीगढ़ के पैटर्न पर साफ्टवेयर बनाने की बात कही है। इसके तहत सूबे के करीब 40 लाख किसानों का डाटा साफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इसमें बैंक खातों से आधार लिंकअप वाले किसानों को पात्रता दी जाएगी। इसमें आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए।

बैंकों से रिपोर्ट तलब

सरकार ने बैंकर्स से कर्ज की पूरी रिपोर्ट तलब की है। राज्य स्तरीय कमेटी में भी बैंक प्रतिनिधियों को रखा गया है। कमेटी जल्द ही बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी।

सम्पूर्ण कर्ज		माफी वाला अल्पकालीन कर्ज	
56,377 करोड़ रुपए		कुल किसान	34.00 लाख
किसान 40.96 लाख		कर्ज करीब	38,000 करोड़

85 लाख किसान प्रदेश में, हर साल 52 लाख लेते कर्ज

फाइल फोटो

21.18 लाख किसानों का डूबत कर्ज भी प्रदेश में

14,344 करोड़ का कर्ज डूबत खाते में है अभी

यह होता है अल्पकालीन ऋण

अल्पकालीन ऋण किसान को फसल बुआई के लिए दिया जाता है। यह कर्ज 6 से 18 महीने के लिए होता है। व्यावसायिक बैंक लोन एक साल के लिए देती हैं। इस पर किसान से 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भारत सरकार देती है। इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक अल्पकालीन फसली ऋण छह माह के लिए देती हैं। यह लोन ब्याज मुक्त मिलता है। सहकारी बैंक को 7 प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण सरकार करती है। तीन प्रतिशत केन्द्र और चार प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

अब ऐसे होंगे आवेदन

- निर्धारित दायरे में आने वाले किसानों को पोर्टल पर आवेदन करना होंगे।
- पोर्टल पर केवल उन्हीं किसानों के आवेदन स्वीकार्य होंगे, जिनके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक हैं।
- 02 लाख रुपए तक के ही कर्ज माफ होंगे। इससे औसत प्रति व्यक्ति 60 से 70 हजार किसान कर्ज माफ होगा।
- पोर्टल पर निर्धारित तारीखों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इस समयावधि का निर्धारण हाईपॉवर कमेटी करेगी।
- हाईपॉवर कमेटी नियम बनाएगी। इसमें मौजूदा कर्ज व डूबत कर्ज दोनों माफ होंगे।
- पोर्टल पर आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद सत्यापन होगा। इस सत्यापन की रिपोर्ट के बाद ही कर्ज माफ होगा।

ऐसे तो केवल डिफॉल्टर की मौज

सरकार की कर्जा माफी में सबसे ज्यादा नुकसान उन ईमानदार किसानों को होगा, जो अपने कर्ज की किश्तें वक्त पर चुका रहे हैं। ऐसे किसानों की तादाद भी कम नहीं है, जो 02 लाख रुपए से कम या उससे ज्यादा के कर्ज का भुगतान बैंक या सहकारी संस्थाओं को समयबद्ध ढंग से कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे कर्जदार किसान जो डिफॉल्टर थे, उन्हें इसका पूरा फायदा मिला जाएगा। यानी जो ईमानदारी से कर्ज चुका रहे है, वे खुद को ठगा महसूस करेंगे और जो डिफॉल्टर हैं उन्हें राहत मिल जाएगी।

पंजाब से समझिए यह गणित

किसान, जिनका कर्जा 2 लाख रुपए से ऊपर था, उनकी कर्जा माफी की आस पूरी नहीं हो पाई।

ऋण माफी की योजना से बैंकों का 37 फीसदी एनपीए बढ़ गया, ऋण माफी योजना के बाद।

10 लाख किसान को फायदा मिलना था, मिला 05 लाख को ही।

कर्नाटक ने लगाया शर्तों का अड़ंगा

एक लाख रुपए की सीमा रखी गई। उससे ऊपर की कर्ज राशि ब्याज समेत पहले चुकानी होगी तभी एक लाख रुपए माफ होंगे।

चारा खरीदने के लिए ऋण को माफी के दायरे में नहीं रखा।

सहकारी या सरकारी संस्था में 20 हजार रुपए की नौकरी करने वाले किसान को दायरे से बाहर रखा गया।

साहूकारों के जरिए लिए गए कर्ज को माफ नहीं किया गया।

पहले से चुकाई किस्तें ऋण माफी में समायोजित की गईं।

सरकार का खजाना खाली...

आसान नहीं राह, पहले करना होगा बजट प्रावधान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रदेश में कर्ज माफी की राह आसान नहीं है। सरकार का खजाना खाली है, ऐसे में 35 से 38 हजार करोड़ का बोझ उठाना सरकार की आर्थिक स्थिति को बेपटरी कर सकता है। सरकार को पहले अनुपूरक बजट में कुछ प्रावधान करने होंगे, इसके बाद अगले वित्तीय सत्र में बजट प्रावधान किए जाएंगे। सरकारी बैंक बिना बजट प्रावधान के इस माफी को मानने से इंकार कर सकते हैं। सरकार कर्ज माफी से प्रभावित किसानों का आकलन कर सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए बजट प्रावधान करेगी। सहकारी बैंक राज्य का विषय है इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्र के अधीन हैं। इनके ऋण माफ करने के लिए पहले बजट उपलब्ध कराना होगा। पंजाब और कर्नाटक में यही समस्या सामने आ रही है। भाजपा सरकार के समय भी ऐसा ही हुआ था। नए लोन माफ करने से पहले वर्तमान सरकार को बैंकों के बकाया करीब 6 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था भी करनी होगी। सरकार ने करीब आठ हजार करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। सरकार ने इसके लिए मात्र दो हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। 2200 करोड़ अपेक्स बैंक ने एनसीडीसी से लोन लिया है तथा अन्य रकम सरकार के प्रति बकाया हैं।

कौटिल्य एकेडमी

पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा व्यापक स्तर पर तेज गति से होने वाला कंस्ट्रक्शन

विश्व में कुल कार्बन उत्सर्जन का 8 फीसदी हिस्सा सीमेंट का

पूरी दुनिया के जगमगाते शहर दरअसल सीमेंट-कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। यह पानी के बाद दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला संसाधन है। यह कार्बन उत्सर्जन के प्रमुख कारकों में से एक है। विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का 8 फीसदी सीमेंट से ही होता है। सीमेंट से पर्यावरण को होने वाला नुकसान वर्तमान समय में वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। जानें पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे सीमेंट से जुड़ी बातें और इस समस्या के समाधान क्या हो सकते हैं?

हाल ही में बड़े सीमेंट उद्योगपति पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-सीओपी24 में जुटे। यहां जलवायु परिवर्तन के लिए हुए पेरिस समझौते की जरूरतों को पूरा करने के तरीकों पर विमर्श हुआ। दरअसल, सीमेंट कंक्रीट का मुख्य घटक है। अगर सीमेंट उद्योग एक देश होता, तो यह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक होता। कार्बन उत्सर्जन में विमानन ईंधन का योगदान 2.5% से ज्यादा है।

दुनिया की भव्य इमारतों में सीमेंट कंक्रीट का उपयोग

अधिकतर टॉवर, कार पार्किंग, पुल और बांध में सबसे प्रमुख सामग्री के तौर पर कंक्रीट का उपयोग होता है। कंक्रीट से ही दुनिया की सबसे अधिक आकर्षक इमारतें भी बनी हैं। इनमें सिडनी ओपेरा हाउस, दिल्ली का कमल मंदिर, दुबई का बुर्ज खलीफा आदि शामिल हैं। इनकी मजबूती के पीछे सिर्फ इनमें इस्तेमाल हुई सामग्री है। रेत, बजरी, सीमेंट और पानी का मिश्रण यानी कंक्रीट को आर्किटेक्ट, डेवलपर्स और बिल्डर काफी पसंद करते हैं।

1990 के बाद से सीमेंट उत्पादन में 4 गुना बढ़ोतरी

सीमेंट की कुछ ऐसी अनूठी खासियतें हैं जिन्होंने 1950 के दशक से वैश्विक सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है। एशिया और चीन में 1990 के बाद से इस क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। 1950 के बाद से उत्पादन में 30 गुना और 1990 के बाद से चार गुना बढ़ोतरी हुई है। 20वीं सदी में चीन ने 2011 से 2013 के बीच सीमेंट का अमेरिका से भी ज्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि चीन में अब इसकी खपत में वृद्धि रुक गई है। दक्षिण-पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका इसके नए उभरते बाजार हैं। यहां बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक विकास के चलते तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगले 40 सालों में दुनिया की इमारतों का फ्लोर एरिया (जमीन का क्षेत्रफल) दोगुना होने का अनुमान है। इसके लिए साल 2030 तक सीमेंट के उत्पादन में एक चौथाई वृद्धि की जरूरत होगी।

8 हजार वर्ष पहले भी उपयोग होता था कंक्रीट

माना जाता है कि सबसे पहले कंक्रीट का इस्तेमाल 8 हजार साल पहले हुआ था। सीरिया और जॉर्डन के व्यापारी फर्श, इमारतें और जमीन के नीचे जलाशय बनाने में कंक्रीट का इस्तेमाल करते थे। बाद में रोमन कंक्रीट के महारथी के तौर पर जाने जाने लगे। उन्होंने 113-125 ई. में पैनतिअन का निर्माण किया, जो बिना किसी सहारे के खड़ा 43 मीटर डायमीटर वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट का गुंबद है। लेकिन, आधुनिक समय में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उसका काफी हद तक श्रेय 19वीं सदी में लीड्स के जोसफ एस्पिन की पेटेंट कराई गई प्रक्रिया को जाता है।

क्या है पोर्टलैंड सीमेंट

उनकी चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी को ओवन में गर्म करने और फिर 'कृत्रिम पत्थर' बनाने के लिए उसे पीसकर पाउडर बनाने की नई तकनीक को अब पोर्टलैंड सीमेंट के तौर जाना जाता है। इसके सर्वव्यापी इस्तेमाल के बावजूद पिछले कुछ दशकों में कंक्रीट के पर्यावरणीय प्रभाव का परीक्षण बढ़ गया है। पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में सिर्फ धूल पैदा करने वाला उत्खनन शामिल नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत बड़ी भट्टियों की भी जरूरत होती है, जिनमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीमेंट बनाने की वास्तविक रासायनिक प्रक्रिया से उच्च स्तर तक कार्बन उत्सर्जित होती है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है।

क्या हो सकता है समाधान

पिछले कुछ दशकों में नए संयंत्रों की ऊर्जा कुशलता में सुधार और जीवाश्म ईंधन की बजाय अपशिष्ट सामग्री जलाने से प्रति टन उत्पादन में औसत कार्बन उत्सर्जन 18 फीसदी घट गया है। नई स्थापित ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन (जीसीसीए) भी सीओपी24 में शामिल हुई। यह एसोसिएशन दुनिया की सीमेंट उत्पादन क्षमता के 35% का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है तो इसकी उम्मीद सीमेंट बनाने की प्रक्रिया को ठीक करने में ही बची हुई है। उसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ-साथ प्रक्रिया में सुधार पर भी ध्यान देना होगा।

क्लिंकर: एक बड़ा प्रदूषक

क्लिंकर(सीमेंट के ढेले) सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन 'क्लिंकर' बनाने की प्रक्रिया से ही होता है। कच्चा माल, खासतौर पर चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी, इनका उत्खनन किया जाता है और फिर पीसा जाता है। पिसे हुए कच्चे माल को अन्य लौह अयस्क या राख जैसी सामग्री के साथ मिलाया जाता है। क्लिंकर ठंडा, पिसा हुआ और जिप्सम व चूना पत्थर के साथ मिश्रित होता है। साल 2016 में, वैश्विक सीमेंट उत्पादन में 2.2 अरब टन कार्बनडाय ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जो वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित होने वाली कार्बनडाय ऑक्साइड का 8 फीसदी है। थर्मल दहन के साथ इस क्षेत्र के कुल उत्सर्जन का 90% क्लिंकर के उत्पादन से होता है।

सीमेंट का क्या विकल्प

सीमेंट बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी नए सीमेंट के विकल्प को बढ़ावा दे रही है, यह उत्तरी कैरोलिना में एक नया स्टार्टअप है, जो बायो कंक्रीट ईंटों के विकास में खरबों बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक में मोल्ड्स में रेत डाली जाती है और उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इंजेक्ट किए जाते हैं। यह मूंगा बनाने जैसी प्रक्रिया को शुरू कर देता है।

Expert

सीमेंट बनाने की प्रक्रिया से बढ़ती है वातावरण में गर्मी

भारत गर्म जलवायु वाला देश है। यहां पहले जो पारंपरिक निर्माण होते थे। उनमें मिट्टी, गारे का इस्तेमाल होता था। वो गर्मी में भी ठंडक का अहसास देते थे, लेकिन विकास की तेज रफ्तार से बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के कारण सीमेंट आधारित निर्माण तेज हो गया। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया से हीट जनरेशन यानी उष्मा सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है। यह जलवायु के लिए बहुत हानिकारक है। हम विकासशील देश हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में सीमेंट की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विकसित देशों में अब सीमेंट आधारित निर्माण पर लगाम कसी जा रही है। सीमेंट आधारित निर्माण के कारण उस क्षेत्र में धूल भी जनरेट होती है। इस कारण जो नियम बने हैं कि उन जगहों पर रोड लगाए जाएं, श्रमिक नियमित रूप से मॉस्क पहनें, लेकिन इन नियमों का कहीं पर पालन नहीं किया जा रहा है।

-मीना जावेद, पर्यावरणविद

कौटिल्य एकेडमी

जीवन बचाने के लिए 36वीं बार इंदौर ने दिया रास्ता, अमूमन हर महीने ऐसा करते हैं हम

तस्वीर विजय नगर चौराहे की है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल से अंग ले जा रही एम्बुलेंस को ट्रैफिक रोककर रास्ता दिया गया। फोटो : ओपी सोनी

KAUTILYA ACADEMY INDORE

बॉम्बे हॉस्पिटल से बने तीन ग्रीन कॉरिडोर

पहला कॉरिडोर : बुधवार दोपहर 3.50 बजे लंग्स और हार्ट लेकर एम्बुलेंस बॉम्बे हॉस्पिटल से रवाना होकर 4.07 बजे एयरपोर्ट पहुंची। यहां से दोनों अंग प्लेन से मुंबई भेजे गए। वहां दोनों अंग 27 वर्षीय युवती को ट्रांसप्लांट किए गए।

दूसरा कॉरिडोर : शाम 4.10 बजे लिवर भेजा गया, जो पांच मिनट में सीएचएल अस्पताल पहुंच गया। इसे 57 वर्षीय पुरुष को लगाया गया। ये 1984 से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे।

तीसरा कॉरिडोर : 4.29 बजे दोनों किडनियां लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई। यह 13 मिनट में चोइथराम अस्पताल पहुंची। किडनियां 30 वर्षीय युवक और 53 वर्षीय महिला को दी गई।

कौटिल्य एकेडमी

What's wrong in reserving jobs for locals, asks Nath

Shivraj Tweets: 'In MP, There Is No Outsider'

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: Chief minister Kamal Nath — who is at the centre of a controversy over his remarks on UP-Bihar migrants — strongly defended his decision to incentivise hiring of MP domiciles by saying that there was nothing new in having a job preference policy for locals.

▶CM pitches for weekly off for cops: P 5

"Such policy exists in other states also. Is it not there in Gujarat? What's new in it?" Nath said at a press conference after chairing his first meeting with IPS officers at the police HQ on Wednesday. "States like Gujarat have policies giving employment preference to locals," said the CM, holding his ground despite an all-out attack by BJP, even branding him an outsider.

In the middle of this tussle, former CM Shivraj Singh Chouhan dropped a gem of a tweet. "Madhya Pradesh mein na koi idhar ka hai, na udhar ka hai. Madhya Pradesh mein jo bhi ata hai, yahan ka ho kar hi bas jata hai. Pradesh ko Hindustan ka dil aise hi nahin kahte. Kyun, thik hai na (In Madhya Pradesh, there is no outsider. Whoever comes to MP settles down here and becomes one with the state. It's not for nothing that MP is called the heart of Hindustan. Isn't it?)," tweeted Chouhan.

▶Continued on P 5

WHO GETS WHAT POST

- **ASHOK BARNWAL** (1991 **batch**) | Principal secretary & public service administration
- **PRAMOD AGRAWAL** (1991 **batch**) | Urban development and housing department; Administrator of Capital Project Authority; MD of Metro Rail Company Limited & additional charge of science and technology department
- **VIVEK AGRAWAL** (1994 **batch**) | PHE department & MS, Madhya Pradesh Jal Nigam
- **HARIRANJAN RAO** (1994 **batch**) | Tourism, technical education, skill development & employment departments
- **RENU TIWARI** | Secretary, culture department; commissioner-cum-director of Swaraj Sansthan & trusty of Bharat Bhawan
- **MANOJ SHRIVASTAVA** (1987 **batch**) | Vice-chancellor of Sanchi University
- **P NARHARI** (2001 **batch**) | Addl charge of MD, MP Madhyam & commissioner of state aviation

Chief minister Kamal Nath dissolved boards and corporations in the state with immediate effect. The appointments were made by BJP-ruled government. After the change of the guard, chairpersons of some boards and corporations had resigned. With fresh order, all political appointments in authorities, corporations, board and councils stand cancelled

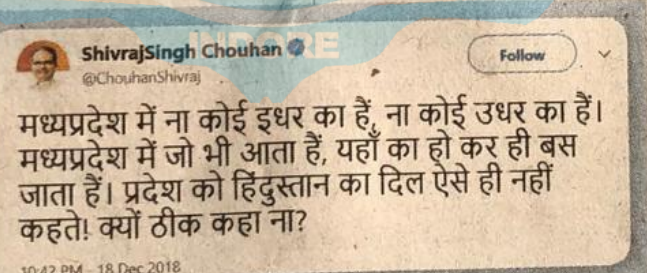

कौटिल्य एकेडमी

To Kill A Moving Story

Why Kamal Nath and other CMs like Rupani are so wrong on reserving jobs for locals

Saubhik.Chakrabarti@timesgroup.com

Kamal Nath started his tenure as Madhya Pradesh chief minister posing as an anti-migrant, thereby landing himself in a soup and putting his party's national chief, Rahul Gandhi, in a bit of a pickle.

Surprisingly for such a veteran politician, Nath's jobs-for-local-boys (no incentives for industry without 70% local employment) pitch lacked the minimum of political sense or grace. By dissing migrants from Bihar and UP, he made Congress look foolish at best in these two electorally vital states. By forgetting that he himself is not MP-born and that he got the CM's job by edging out a local born, Jyotiraditya Scindia, he invited a fair measure of ridicule. And by ignoring the fact that MP is also a big source of inter-state migration in the country, the CM may have put migrants from his own state in the crosshairs of other state administrations.

But Nath and CMs from other parties, BJP included, who champion exclusionary policies against non-local born Indians are guilty of much more than political ineptitude – they are a potential risk to economic well-being and efficiency.

Here's a piece of data that CMs like Nath and Gujarat's BJP CM, Vijay Rupani, who proposed not too long back a law that makes 80% local employment mandatory for any firm, as well as all Maharashtra politicians, should know: India is among the *worst performers* in the world when it comes to inter-state migration.

China, which doesn't set much store on constitutional rights, has a system called 'hukou' that restricts migration. But even then democratic India, that doesn't restrict movement, performs worse than its totalitarian neighbour when it comes to how freely people move across provincial borders.

India ranked last in a list of 80 countries in what experts called migration intensity, a measure of how easily people move within a country to settle down in a place they were not born in. (bit.ly/2R8vtCL). So, Nath and others should know that their rhetoric against people from other states is fundamentally misplaced.

Uday Deb

The Economic Survey of 2017 had sought to enthusiastically argue that inter-state migration rates in India are fast increasing. But as many experts had pointed out, some of the Survey's analytics were questionable; for example, see this analysis in ET by Amitabh Kundu and PC Mohanan, (bit.ly/2GrWgpm). Basically, headline data that suggests 30% of India's population are migrants hides the fact that two-thirds of this is inter-state migration, and a big chunk of movements across state borders is accounted for by women moving post-marriage.

So, India is far from being an integrated labour market, and politicians like Nath and Rupani exaggerate the migrants-taking-locals'-jobs issue to serve populist electoral aims. But the fact is that India will benefit immensely from more, not less, internal migration.

Even a quick study of any successful development and growth episode in any major country will show high internal migration accompanied these positive economic experiences. The reasons are simple. Hjgh migration rates mean the labour market can efficiently match workers to jobs.

Look at this list – it's India at work, north, south, east and west. If jobs are reserved for locals, and if more populist restrictions follow, India will become a hostile labour market for poor Indians

Construction in the national capital region attracts migrant labour, including from MP, because locals don't want these jobs. Farms in Punjab and Haryana attract migrant labour. Domestic services in all major urban centres will get terribly affected without migrant labour. Gujarat CM Rupani should know that Ahmedabad's thriving local economy has a huge contribution from a migrant labour force that's over 1.5 million, according to NGO Ajeevika Bureau.

Uttar Pradesh, Bihar, MP, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand, Jammu & Kashmir and West Bengal, data shows, are major sources of migrant labour and states that are favoured destinations are, Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala.

Look at this list – it's India at work, north, south, east and west. If jobs are reserved for locals, and if more populist restrictions follow, India will become a hostile labour market for poor Indians. And if internal labour movement gets restricted, growth will, over time, suffer, as will the fight against poverty.

There's also the social aspect. Nath and Rupani style exclusionary policy against migrants risks creating social tensions in a country where social relations in many areas are already a tinderbox, awaiting a political spark. We have caste and religious tensions, and now do we want to add local versus non-local tensions to that?

Enlightened policy will in fact foster higher rates of internal migration and recognise that non-portability of welfare benefits across state boundaries is a major reason for relatively low inter-state labour movement (see this paper, bit.ly/2R8vtCL).

Poor Indians get patchy welfare benefits from state administrators if they are domiciled in the state. If they move to another state, they lose most of those because states don't recognise migrants as legitimate welfare recipients. With Aadhaar now almost universal in India, and with welfare provisioning linked to Aadhaar, policy makers must seriously think of making benefits portable across state boundaries.

Will this happen? Not any time soon, probably. State level politics is getting hypercompetitive. And for some parties, Congress, for example, hyper local populism may make electoral sense even for national politics. Congress may calculate that instead of allowing BJP to make 2019 polls a Narendra Modi versus Rahul Gandhi battle, it will concentrate on making the general election a sum of local fights. In that case, Kamal Nath may have done what some other Congress local leaders will do later.

For India to grow faster, Indians must move more. But politics may yet kill this moving story.